

बैर व लार  
हकाम जो  
प की लार  
जारी डर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या- 19/2019

चैनाराम पुत्र सरदाराराम जाति बावरी निवासी चक 19 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जरिये पैरोकार राज.।

.....रेसपोण्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री दलवीरसिंह सोवना, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर

— :: निर्णय :: —

दिनांक:- 18.11.2020

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 03.07.2018 जिसके द्वारा जरिये मिसल संख्या 13/2018 व 7/18 अनवान चैनाराम बनाम सरकार में चक 19 एएस का पत्थर न. 235/466 का किला न. 1 ता 25 =25.00 बीघा की वसीयत अनुसार इंतकाल करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, के विरुद्ध 21.06.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपीला के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के चाचा पेमा पुत्र जीवा बावरी के नाम से चक 19 ए.एस. में पत्थर नम्बर 235/466 का 25 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन थी जो उसी के कब्जा काशत में थी। पेमा शादीशुदा नहीं होने से उसके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वह अपीलान्ट के ही साथ रहता था व अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने को आवंटित जैर अपील भूमि की वसीयत प्रार्थी के नाम रोबरू गवाहान दिनांक 19.05.1979 को करवा दी थी। अपीलार्थी के चाचा पेमा का स्वर्गवास दिनांक 08.10.1990 को हो गया व भूमि का कब्जा तब से ही अपीलार्थी के पास चला आ रहा है। अपीलार्थी ने उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर कर अखबार में सूचना जारी की गई व आगे की कार्यवाही हेतु पत्रावली सुनवाई में रखी गई। पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को शिविर में ग्राम पंचायत कूपली कैम्प में रखी गई परन्तु उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई व उस दिन अपीलार्थी की गैर हाजरी दिखाकर पत्रावली का निर्णय दिनांक 03.07.2018 को करते हुए जैरअपील आदेश के द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया तथा उक्त फैसला में धन्नाराम व कालूराम का कब्जा होना गलत बताया व भूमि बेचान करने के तथ्य को भी गलत बताया। चूंकि भूमि अपीलार्थी के नाम रिकार्ड में दर्ज हुए बिना बैयनामा हो ही नहीं



अशोक कुमार  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

सकता। अदालत मातहत ने अपने ही कयासो के आधार पर जैर अपील फैसला गैरकानूनी रूप से पारित किया है जो निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दलवीर सिंह सोवना एवं रेस्पोंडेंट पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री दलवीर सिंह सोवना ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के चाचा पेमा पुत्र जीवा बावरी के नाम से चक 19 ए.एस. में पत्थर नम्बर 235/466 का 25 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन थी जो उसी के कब्जा काशत में थी। पेमा शादीशुदा नहीं होने से उसके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वह अपीलान्ट के ही साथ रहता था व अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने को आवंटित जैर अपील भूमि की वसीयत प्रार्थी के नाम रोबरू गवाहान दिनांक 19.05.1979 को करवा दी थी। अपीलार्थी के चाचा पेमा का स्वर्गवास दिनांक 08.10.1990 को हो गया व भूमि का कब्जा तब से ही अपीलार्थी के पास चला आ रहा है। अपीलार्थी ने उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर कर अखबार में सूचना जारी की गई व आगे की कार्यवाही हेतु पत्रावली सुनवाई में रखी गई। पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को शिविर में ग्राम पंचायत कूपली कैम्प में रखी गई परन्तु उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई व उस दिन अपीलार्थी की गैर हाजरी दिखाकर पत्रावली का निर्णय दिनांक 03.07.2018 को करते हुए जैर अपील आदेश के द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया उक्त फैसला में धन्नाराम व कालूराम का कब्जा होना गलत बताया है व भूमि बेचान करने के तथ्य को भी गलत बताया है चूंकि भूमि अपीलार्थी के नाम रिकार्ड में दर्ज हुए बिना बैयनामा हो ही नहीं सकता। जैर अपील रकबा का कब्जा वसीयत के दिन से ही उसके पास है भूमि की तमाम किश्ते खजाना राज में जमा करवाई हुई होने से खातेदारी सरकार को जारी करनी है अपीलान्ट या आवंटी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2006 पेज 133 का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि जब समस्त किश्ते जमा हो गई व खातेदारी जारी करने का समय पूरा हो गया तो कानूनी रूप से वह रकबा खातेदारी ही माना जावेगा भूमि का आगे बेचान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। चूंकि दूसरा कोई पक्षकार इस रकबा का अधिपत्य ही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वसीयत के मुताबिक इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया जावे।
5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत व पूर्ण जांच उपरांत ही पारित किया गया है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय में उक्त रकबा को गैर खातेदारी मानकर उक्त आदेश पारित किया है। हमने पत्रावली में उपलब्ध इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 25/2014 अनवान सुमित्राबाई आदि बनाम जागरसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2004 अनुसार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 में दिनांक 05.05.1984 से पूर्व हस्तान्तरण के प्रकाश में वसीयत का उल्लेख होने से तथा उन पर आधारित है। संसोधन दिनांक 05.05.1984 द्वारा हस्तान्तरण के प्रकार से वसीयत शब्द को हटा दिया था। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान प्रभावी है। इस प्रकार धारा 13 के प्रावधानों के प्रकाश में आरटीए की धारा 39 कॉलोनी ऐरिया में स्थित भूमि पर लागू नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा आवंटन होने के बाद समस्त किश्ते जमा होकर खातेदारी जारी करने की

अदालत मातहत  
सू.सं. 181-1-1-1-2014



समय अवधि पूरी होने के बाद रकबा कानूनी रूप से खातेदारी के रूप में ही देखा जावेगा।  
आंवटी की मृत्यु हो चुकी है व वसीयतग्रहिता के पक्ष में भी इन्तकाल नहीं करने से किसी भी  
व्यक्ति के अधिकार खाली नहीं रह सकते। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार जैर अपील रकबा  
पर किसी भी सक्षम अदालत का स्थगन आदेश नहीं है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीविजयनगर को रिमाण्ड कर  
निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमों का अवलोकन कर एवं प्रार्थी को पुनः सुन कर  
पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड  
लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अपील नम्बर 1811/20  
अतिरिक्त जिल्द कलेक्टर  
अतिरिक्त जिल्द कलेक्टर  
सूरतगढ़ श्री विजयनगर कलेक्टर  
सूरतगढ़